बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 108 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 06 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

कल यार गद्दार पर बवाल, आज फिर आमने-सामने, राहुल गांधी के करीब से गुजरे बिट्टू ने कसा तंज

नई दिल्ली । लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू गुरुवार को फिर आमने सामने आए. विवाद के बाद आज राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू दोनों मकर द्वार पर दिखे. दिलचस्प बात यह रही कि दोनों ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे. इस संयोग पर बिट्टू ने कांग्रेस पर तंज कसा. राहुल गांधी ने एक दिन पहले रवनीत बिट्टू को गद्दार कह दिया था और फिर उसके बाद उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की थी. हालांकि रवनीत बिट्टू ने उनसे हाथ नहीं मिलाया और उन्हें देश का दुश्मन बताया था. संसद परिसर में यार गद्दार का ये मामला खूब गरमाया था और बीजेपी ने इसे सिखों का अपमान बताया था.

खरगे और राहुल गांधी की कांग्रेस की बंगाल इकाई के नेताओं के साथ बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक अहम बैठक की। बैठक में कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यह बैठक राय के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नई दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग पर हुई। पश्चिम बंगाल में राजनीति गरमाई हुई है। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से चुनौती मिल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने कांग्रेस या किसी भी सहयोगी दल के साथ गठबंधन को लेकर अब तक कोई चर्चा शुरू नहीं की है। जबकि टीएमसी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। उधर, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी मंगलवार को नई दिल्ली में पश्चिम

बंगाल के सांसदों के साथ बैठक की। नवीन ने उनकी चिंताओं को सुना। यह बैठक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले हुई है। बैठक के बाद भाजपा सांसद राजू बिस्टा ने कहा कि नितिन नवीन ने सांसदों को मार्गदर्शन दिया और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। भाजपा सांसद राजू बिस्टा ने बताया कि बैठक में पश्चिम बंगाल से लोकसभा और राज्यसभा के हमारे सभी सांसद और पहली बार चुने गए सांसद भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दो घंटे से ज्यादा समय बिताने का मौका मिला। उन्होंने अपनी चिंताओं पर चर्चा की। बिस्टा ने कहा कि यह पूरी तरह से संगठन की बैठक थी। उनसे यह हमारी पहली मुलाकात थी, इसलिए हमें कई सुझाव मिले और काफी मार्गदर्शन मिला। उन्होंने कहा, यही वजह है कि मैं भाजपा को अन्य दलों से अलग मानता हूं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से परिवार जैसे माहौल में मिले। सभी सांसदों ने अपने-अपने मुद्दे रखे।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते थे प्रधानमंत्री- कांग्रेस

नई दिल्ली । कांग्रेस ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि चार दिनों तक निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जानबूझकर बोलने नहीं दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उनकी बात सुनना नहीं चाहते थे।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 10 जून, 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सदन में बोलने से रोका गया था, जबकि उस वक्त राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा पूरी हुई थी। लोकसभा ने बृहस्पतिवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में हुई चर्चा का प्रधानमंत्री द्वारा सदन में जवाब देने की परंपरा है, लेकिन

गतिरोध की स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जवाब लोकसभा में नहीं हुआ और प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। रमेश ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा में बोलने से चार दिनों तक रोका गया। वह राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीति को लेकर कुछ बुनियादी बात करने वाले थे, लेकिन उन्हें जनाबूझकर रोक दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बातें सुनना नहीं चाहते थे। उनका कहना था, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी को बोलने से रोके जाने का विषय उच्च सदन में उठाया और कहा कि संसद के दो स्तंभ होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। जब एक स्तंभ पर आक्रमण होता है दूसरा स्तंभ भी कमजोर होता है। रमेश ने कहा कि इस विषय पर विपक्षी दल एकजुट हैं और उन्होंने राज्यसभा से बहिर्गमन किया। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक और आसन की अवमानना के मामले में वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित सांसद मणिकम टैगोर ने पीटीआई-वीडियो से कहा, सदन में दो आवाजें हैं, एक आवाज सत्तापक्ष की और दूसरी विपक्ष की है। लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष की आवाज को मौका मिले। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, यह सरकार की मन की बात वाली सोच है। मन की बात रेडियो पर हो सकती है, लेकिन संसद मन की बात के लिए नहीं है। संसद में विपक्ष के नेता बोलते हैं और फिर प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। टैगोर ने कहा कि यह पहली बार है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया और प्रधानमंत्री भी नहीं बोले, जो लोकतंत्र के लिए दुखद है।

मनोज तिवारी का आरोप- विपक्ष साजिश के तहत पीएम मोदी को बोलने नहीं दे रहा, ये जनता के पैसे की बर्बादी

नई दिल्ली । भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष एक साजिश के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बजट पर बोलने नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद के माध्यम से बजट के महत्वपूर्ण प्रावधान जनता को बताना चाहती है, लेकिन विपक्ष व्यर्थ के मुद्दों को उठाकर जनता का पैसा बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष महिला सांसदों को आगे रखकर किसी अप्रिय घटना को अंजाम देना चाहती थी, लेकिन सत्तापक्ष ने समझदारी से इसे टाल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को उचित नहीं कहा जा सकता। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब तक लोगों को बजट से केवल टैक्स छूट की जानकारी मिलने की ही उम्मीद रहती थी। यह छूट भी थोड़ी-बहुत ही हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले वर्ष 12 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह करमुक्त कर दिया। इससे आम लोगों को बड़ा लाभ हुआ। व्यावहारिक रूप से 12.75 लाख रुपए वार्षिक कमाने वालों को अब कोई कर नहीं चुकाना पड़ता। भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने कहा कि इस बजट की एक बड़ी विशेषता हर जिले में स्किल सेंटर स्थापित करना है। इससे बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हर राय और हर जिले में लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे सबसे निचले स्तर के लोगों को मजबूती दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ज्ञान (GYAN यानी युवा, महिला, किसान और गरीब) के चार वर्गों की बात की थी। सरकार बजट के माध्यम से इन सभी चारों वर्गों के कल्याण की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, डाटा संरक्षण और माइक्रोचिप आधारित अर्थव्यवस्था का है। बजट के माध्यम से देश को इसी दिशा में ले जाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इससे भारत आने वाले समय में एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने नियमों में बदलाव कर व्यापार करने की तकनीकी और कानूनी अड़चनों को दूर किया गया है।

26 जनवरी से पहले दिल्ली में लिखे थे स्लोगन...कनाडा में रची गई पूरी साजिश; दो गिरफ्तार

नई दिल्ली । 26 जनवरी से पहले दिल्ली में दो स्थानों पर लिखे मिले प्रो-खालिस्तान नारों की घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक एंबुलेंस ड्राइवर बलजिंदर और उसके सहयोगी रोहित उर्फ किरात को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अनुसार सिख्स फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नून के एक करीबी सहयोगी ने दोनों आरोपियों को यह काम करने के लिए हायर किया था। जानकारी के अनुसार पूरा प्लान कनाडा में रचा गया था और इस काम के लिए पन्नून ने दो लाख रुपये देने की पेशकश की थी। पुलिस के अनुसार मास्टरमाइंड, जो तिलक नगर का निवासी है, 26 जनवरी से कुछ दिन पहले कनाडा चला गया था और पन्नून के सीधे संपर्क में था। दिल्ली में 26 जनवरी से पहले दो स्थानों पर लिखे मिले प्रो-खालिस्तान नारों के मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान एंबुलेंस ड्राइवर बलजिंदर और उसके सहयोगी रोहित उर्फ किरात के रूप में हुई है। स्पेशल सेल के मुताबिक, सिख्स फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नून के एक करीबी सहयोगी ने दोनों को इस काम के लिए हायर किया था। जांच में सामने आया है कि पूरी साजिश कनाडा में रची गई थी और इस काम को अंजाम देने के लिए पन्नून की ओर से दो लाख रुपये देने की पेशकश की गई थी। पुलिस के अनुसार, इस मामले का मास्टरमाइंड तिलक नगर का रहने वाला है, जो 26 जनवरी से कुछ दिन पहले ही कनाडा चला गया था। वहीं से वह पन्नून के सीधे संपर्क में रहकर पूरी साजिश को संचालित कर रहा था। फिलहाल स्पेशल सेल आगे की जांच में जुटी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- मेडिकल छात्र के दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर पर रोक रद्द, एनएमसी को नीति बनाने का निर्देश

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल छात्र के एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर या माइग्रेशन पर पूर्ण प्रतिबंध को अमान्य करार दिया है। साथ ही नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) को आवश्यक शर्तों के साथ माइग्रेशन की अनुमति देने हेतु उचित नीति बनाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2023 का रेगुलेशन 18 स्पष्ट रूप से अविवेकपूर्ण और मनमाना होने के कारण संविधान के खिलाफ है। पीठ ने यह फैसला 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित एक मेडिकल छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर से दिल्ली के एक कॉलेज में माइग्रेशन की मांग की थी। राहत देते हुए अदालत ने एनएमसी को याचिकाकर्ता के ट्रांसफर आवेदन पर तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का

निर्देश दिया। अदालत ने चार फरवरी को दिए अपने निर्णय में कहा कि मेडिकल शिक्षा संस्थानों में एकरूपता, मानक और अखंडता बनाए रखने के नाम पर ट्रांसफर या माइग्रेशन पर पूर्ण प्रतिबंध, जिसकी आवश्यकता विभिन्न परिस्थितियों में पड़ सकती है, उचित नहीं कहा जा सकता। अदालत की राय में ऐसा प्रतिबंध स्पष्ट रूप से अविवेकपूर्ण और मनमाना है। अदालत ने यह भी कहा कि माइग्रेशन के दुरुपयोग की आशंका का एनएमसी का तर्क टिकाऊ नहीं है, क्योंकि दुरुपयोग की संभावना के आधार पर किसी नागरिक के वैध अधिकारों से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने नोट किया कि बाड़मेर की कठोर जलवायु के कारण याचिकाकर्ता की चिकित्सीय स्थिति और क्षमताएं प्रभावित हो रही थीं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक निकायों का दायित्व है कि दिव्यांग व्यक्तियों को उचित सुविधा और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास बाड़मेर के सरकारी कॉलेज की सीट लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह उसकी कम मेरिट के कारण नहीं, बल्कि उसे काउंसलिंग के शुरुआती चरणों में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही वह अंतिम चरण में काउंसलिंग में शामिल हो सका, जब विकल्प सीमित रह गए थे। अदालत ने कहा कि युक्तिसंगतता समानता का एक पहलू है, इसलिए राय या उसकी संस्थाओं के हर निर्णय में युक्तिसंगतता होनी चाहिए। उपरोक्त चर्चा के आधार पर 2023 के रेगुलेशन 18 को संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा नहीं पाया गया और इसे स्पष्ट रूप से अविवेकपूर्ण व मनमाना मानते हुए अल्ट्रा वायर्स घोषित किया जाता है। अतः ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2023 का रेगुलेशन 18 अमान्य घोषित किया जाता है।

पंजाब की राजनीति में डेरों का असर

पंजाब की राजनीति में डेरों का प्रभाव कोई नई बात नहीं है, यह सालों से चलता आ रहा है। असल में डेरों की शुरुआत अंग्रेजों के समय से हुई जब उन्होंने सिखों की ताकत को कम करने के लिए, उन्हें गुरु ग्रन्थ साहिब से तोड़कर डेरों की ओर अग्रसर किया। देखते ही देखते सिख समुदाय के ज्यादातर लोगों का रुख डेरों की ओर बढ़ने लगा क्योंकि जितने भी डेरे खोले गए हैं उनमें से ज्यादातर डेरों के संचालक सिख समुदाय से ही लिए जाते। इतना ही नहीं डेरों के अन्दर गुरबाणी कीर्तन या गुरु ग्रन्थ साहिब से पंक्तियां लेकर उन्हें इधर-उधर जोड़कर लोगों को लुभाने का कार्य किया जाता। आज तक किसी भी डेरे के द्वारा अपनी बाणी नहीं लिखी गई। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि पंजाब केवल खेत-खलिहानों और गुरुओं की धरती ही नहीं है, बल्कि यह डेरों की संस्कृति का भी बड़ा केंद्र बन चुका है। समय के साथ-साथ यह डेरे सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं रहे, बल्कि उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी गहरी दखलअंदाज़ी शुरू कर दी। आज पंजाब की राजनीति को समझने के लिए डेरों के प्रभाव को समझना बेहद जरूरी है। अनौपचारिक आंकड़े बताते हैं कि पंजाब के 13 हजार में से 9 हजार गांवों में डेरों का प्रभाव है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को यह लगता है कि बिना डेरों से जुड़े उनका राजनीति में आगे बढ़ना सम्भव नहीं है जिसके चलते वह डेरों में हाजरियां भरते हैं। कांग्रेस, भाजपा, आप से लेकर स्वयं को पंथक कहलाने वाली पार्टी शिरोमणि अकाली दल के ज्यादातर नेतागण भी लम्बे समय से ऐसा ही करते आ रहे हैं। असल में डेरों के द्वारा सामाजिक सेवाएं कर राजनीतिक पहचान बनाई जाती है जैसे शिक्षा, नशा-मुक्ति, लंगर और स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। इससे लोगों में भरोसा बनता है और वही भरोसा चुनाव के समय राजनीतिक फैसले में बदल जाता है। आज पंजाब में वैसे तो सैकड़ों डेरे चल रहे हैं मगर उनमें से कुछ प्रमुख हैं जिनमें डेरा सच्चा सौदा, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, निरंकारी मिशन, नामधारी पंथ (भैणी साहिब), डेरा बाबा मुराद शाह (नकोदर), डेरा बाबा बालक नाथ, डेरा बल्लां रविदासिया डेरा है जिनके हजारों लाखों अनुयाई हैं और उन्हें डेरों से जो भी आदेश मिलता है वह उसी पर चलते हुए वोट करते हैं और उन्हें देखते हुए ज्यादातर आम वोटर की राय भी बदल जाती है जिससे यह तय माना जाता है कि डेरा प्रमुख की दिव्य दृष्टि जिस पार्टी या नेता पर पड़ गई उसके समर्थन में वोटों की बारिश होना तय है। पंजाब में कई चुनाव ऐसे रहे हैं जहां हार-जीत का अंतर बहुत कम था। ऐसे में डेरों का समर्थन ही तय करता है कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। युवा पीढ़ी भले ही सोशल मीडिया और शिक्षा से जुड़ रही है लेकिन आज भी ग्रामीण पंजाब में डेरों का प्रभाव कम नहीं हुआ है। जब तक सामाजिक असमानता और पहचान की जरूरत बनी रहेगी तब तक डेरों की भूमिका राजनीति में बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पंजाब दौरा और वह भी संत रविदास की जयंती वाले दिन उनके डेरे में जाना पंजाब की राजनीति में होने वाले बदलाव की ओर इशारा करता दिख रहा है। नरेन्द्र मोदी शायद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रविदास भाईचारे के डेरे में जाकर ना सिर्फ हाजरी भरी, बल्कि उन्हें पूर्ण सम्मान भी दिया और आदमपुर हवाई अड्डे का नाम भी संत रविदास के नाम पर रखा गया। देखा जाए तो इस क्षेत्र में 32 प्रतिशत दलित समुदाय के वोट हैं और इस सम्मान के बाद निश्चित तौर पर उनकी सोच भाजपा के प्रति बदलने वाली है। आम तौर पर देखा जाता है कि यह वोट किसी एक पार्टी का ना जाकर इसका बंटवारा होता आया है, पर अब माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस कदम के बाद यह एकतरफा भाजपा के समर्थन में भुगत सकता है जिसके चलते अन्य सभी पार्टियों की चिन्ता बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। आज तक पंजाब में भाजपा अकाली दल की बैसाखी बनकर सरकार बनाती आई है मगर अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने दम पर सरकार बनाने का ख्वाब संजोए हुए है और वह तभी पूरा हो सकता है जब शहरों के साथ साथ गांव देहात का वोट भी भाजपा के हक में भुगते जो कि शुरू से ही एकतरफा शिरोमणि अकाली दल और पिछले चुनाव में आप को मिला। इसी के चलते शायद भाजपा ने अब डेरों का रुख किया और हाल ही में डेरा बल्लां में प्रधानमंत्री ने हाजरी भरी। इससे पूर्व डेरा ब्यास में भी प्रधानमंत्री मोदी होकर आए। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन सीमित था लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कुछ बढ़ौतरी दर्ज की। भाजपा की नजर अब दोआबा क्षेत्र की उन विधानसभा सीटों पर है जहां दलित और रविदासिया मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भाजपा की रणनीति यही संकेत देती है कि पार्टी पंजाब में केवल पारंपरिक शहरी या सीमित वर्गीय राजनीति से बाहर निकलकर व्यापक सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। इसी प्रकार पंजाब के बड़े सियासी चेहरों को भी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। सिख, रविदासिया और दलित समुदाय तक पहुंच बनाना पार्टी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी अपने लिए नया सामाजिक आधार तैयार कर सके। मजीठिया की रिहाई से अकालियों में ऊर्जा विक्रम सिंह मजीठिया की जेल से रिहाई ने वेंटिलेटर पर जाती शिरोमणि अकाली दल को मानो नया जीवनदान दे दिया। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की इच्छा रही होगी कि विक्रम मजीठिया को 2027 के आम चुनावों तक जेल में रखवाया जाए जिससे उन्हें शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ प्रचार करने का पूरा मौका मिले मगर आज जिस प्रकार रिहा होकर मजीठिया ने पहला संदेश टाइगर अभी ज़िंदा है दिया जो सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि राजनीतिक संकेत था। यह संदेश अकाली कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा है और आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए सीधी चुनौती। अब विपक्ष की राजनीति सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सड़क से सदन तक संघर्ष का रूप ले सकती है। पंजाब की सियासत में लंबे समय बाद ऐसा दिन आया जब एक रिहाई ने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी।

मणिपुर में फिर भाजपा सरकार

लगभग एक वर्ष के राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर में पूर्व मंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन हो गया है। उन्होंने बुधवार शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ दो उपमुख्यमंत्री कुकी समुदाय से नेमचा किपगेन और नागा समुदाय से लोसी दिखो ने भी शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के कट्टर आलोचक खेमचंद सिंह को भाजपा नेतृत्व ने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। लम्बे समय से जातीय हिंसा और राजनीतिक अनिश्चितता झेल रहे राज्य में नई सरकार का गठन कर भाजपा ने स्थिति को संतुलित करने के लिए बड़ा दांव खेला है। भाजपा ने मैतेई और कुकी समुदाय के नेताओं को सत्ता में साथ लाने की रणनीति पर काम किया। इसके पीछे सामाजिक संतुलन और शांति बहाली के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा ने कुकी समुदाय से आने वाली महिला नेता नेमचा किपजेन को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया। दोनों समुदायों को सत्ता में प्रतिनिधि देकर बीजेपी राजनीतिक और सामाजिक तनाव कम करके राज्य में स्थिर सरकार देना चाहती है। मणिपुर में नई सरकार का गठन संवैधानिक जरूरत और राजनीतिक अनिवार्यता दोनों ही थी क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि फरवरी में खत्म हो रही है। ऐसे में समय पर सरकार का गठन जरूरी था। नई सरकार बनने से प्रशासनिक फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे और शांति की बहाली की प्रक्रिया मजबूत होगी। 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 37 विधायक हैं और उसके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैतेई-कुकी संघर्ष को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भाजपा क्या संतुलन कायम करती है जिससे शांति बहाली हो सके। मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले युमनाम खेमचंद सिंह की पहचान ऐसे नेता की है जिन्हें हर समुदाय का समर्थन हासिल है। वे हर किसी समूह के साथ जाकर काम कर सकते हैं। उनकी छवि एक सुलझे हुए राजनेता की है जो संगठन और सरकार दोनों का अनुभव रखते हैं। वे 2017 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई विधायी निर्णय लिए और सदन को सुचारू रूप से चलाने का अनुभव प्राप्त किया। 2022 में पुनः बीजेपी सरकार बनने पर उन्हें एन. बीरेन सिंह की कैबिनेट में शामिल किया गया था और उनके पास नगर प्रशासन और आवास विकास, ग्रामीण विकास और पंचायत राज जैसे भारी-भरकम मंत्रालय थे। खेमचंद सिंह को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन हासिल है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। मणिपुर में 3 मई 2023 को जातीय हिंसा शुरू हुई थी जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हुए। हिंसा की शुरुआत तब हुई जब मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने की सिफारिश भेजने को कहा। इस फैसले से पहाड़ी इलाकों में रहने वाली कुकी जनजातियों में असुरक्षा बढ़ी। उनका मानना था कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिलने पर आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। साथ ही घाटी का प्रभाव बढ़कर पहाड़ी इलाकों के प्रभावों को कम करेगा। कुकी लोगों को डर था कि अगर मैतेई लोगों को जनजातीय दर्जा मिल जाता है तो वे और भी ज्यादा हाशिये पर चले जाएंगे। बहुसंख्यक मैतेई मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में बसे हुए हैं जबकि कुकी लोगों की बसावट पहाड़ी इलाकों में है। मणिपुर में भूमि अधिकार, जंगलों का नियंत्रण, सीमा निर्धारण और पुनर्वास जैसे मुद्दे कई वर्षों से विवाद का केन्द्र रहे हैं। कुकी समुदाय का आरोप था कि मैतेई समुदाय उनके अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है। मैतेई समुदाय मुख्यतः हिन्दू है जबकि कुकी अधिकतर ईसाई है। यह पहचान राजनीति में बदल कर संघर्ष को और गहरा कर गई। हिंसा फैली तोपर जले। मंदिरों और चर्चों पर हमले हुए। हजारों लोग विस्थापित हुए। कई जिलों में महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा। इंटरनेट बंद रहा। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। तत्कालीन एन. बीरेन सरकार हिंसा को रोकने में पूरी तरह विफल रही। इस हिंसा ने मणिपुर के समाज को पूरी तरह से बांट दिया। कुकी और मैतेई समुदाय अपनी-अपनी सुरक्षा में लग गए। हालात ऐसे बने कि दोनों समुदायों ने एक-दूसरे के इलाकों में जाना ही बंद कर दिया। कुकी समूहों ने एन. बीरेन पर मैतेई लोगों का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया। अंततः केन्द्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया लेकिन विधानसभा निलम्बित रखी गई। केन्द्र सरकार ने दोनों समुदायों में दूरियां पाटने के लिए बातचीत का सिलसिला शुरू किया। कुकी समुदाय का कहना है कि समस्या का हल सिर्फ शांति प्रक्रिया के दौरान ईमानदारी और गैर पक्षपाती रवैया अपना कर ही हो सकता है। जब तक संसाधनों का समान बंटवारा या केन्द्रीय व्यवस्था नहीं स्थापित होती, समस्या खत्म नहीं होगी और समाधान की प्रक्रिया जटिल बनी रहेगी। इस समस्या से निपटने का टिकाऊ तरीका यही है कि जातीय तनाव की जड़ के जो मुद्दे हैं उन्हें हल किया जाए और ऐसा समाधान किया जाए जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। कुकी में नगा समुदाय भी शामिल है। कुकी और मैतेई समुदायों में तनाव तो अंग्रेजों के शासन से ही चल रहा है। अब जबकि राज्य में फिर से सरकार बन गई है तोउम्मीद की जानी चाहिए कि युमनाम सरकार राज्य में शांति बहाल के प्रयास करेगी और दोनों समुदायों के बीच गहरी हो चुकी अविश्वास की खाई को पाटने के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू करेगी। हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह ने कुकी बहुल इलाकों का दौरा कर शांति और बातचीत की वकालत की थी। मैतेई समुदाय से होने के बावजूद दूसरे समुदायों तक उनकी पहुंच उन्हें मौजूदा संकट में एक स्वीकार्य चेहरा बना सकती है। विवादों से दूर रहने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान बड़ी भूमिका निभा सकती है। जरूरत इस बात की है कि दोनों समुदायों के बीच संवाद कायम हो। जमीन और आरक्षणपर स्पष्ट नीति तैयार की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से तनाव पैदा हो सकता है। कुकी समुदाय को भी कुकीलैंड या जूमलैंड नाम से अलग प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग छोड़नी होगी।

सम्पादकीय...

परीक्षा पे चर्चा - भविष्य के भारत के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना

इस वर्ष 'परीक्षा पे चर्चा' का आयोजन भारत की शिक्षा यात्रा में एक शांत लेकिन निर्णायक बदलाव को रेखांकित करता है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुई यह पहल, जो 2018 में एक एकल वार्षिक संवाद के रूप में शुरू हुई थी, अब एक विश्वव्यापी सामूहिक प्रयास बन गई है, जिसमें विद्यार्थियों के संपूर्ण कल्याण को केंद्र में रखा गया है और माता-पिता व शिक्षक इस साझी जिम्मेदारी के सक्रिय भागीदार हैं। इस वर्ष की भागीदारी का पैमाना इस पहल की गहराई को दर्शाता है। 4.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण के साथ 'परीक्षा पे चर्चा' पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए अब जन-संपर्क से आगे बढ़कर सामूहिक स्वामित्व की एक महत्वपूर्ण स्थिति में प्रवेश कर चुकी है। यह अभूतपूर्व भागीदारी एक सक्षम वातावरण तैयार करने के सामूहिक संकल्प को प्रतिबिंबित करती है, जहां प्रत्येक बच्चा सीख सके, विकसित हो सके और सही मायनों में फल-फूल सके। प्रधानमंत्री के प्रेरक नेतृत्व का प्रदर्शन – प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का शिक्षा, अध्ययन और परीक्षा से जुड़े तनाव जैसे विषयों पर विद्यार्थियों के साथ संवाद, सहानुभूति, व्यावहारिकता और प्रेरणादायक नेतृत्व का एक विशेष तालमेल पेश करता है। औपचारिक प्रोटोकॉल की जटिलताओं से परे जाकर विद्यार्थियों के साथ मार्गदर्शक, मेंटर और शुभचिंतक के रूप में जुड़ने की महान क्षमता प्रधानमंत्री को विशेष बनाती है। यह व्यक्तिगत स्पर्श परीक्षा से जुड़े दबाव को कम करते हुए, एक भरोसेमंद और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है, जहां विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रत्येक बच्चे की विशिष्टता की पहचान – इस प्रयास के केंद्र में एक सरल परंतु बहुत मजबूत सत्य मूल में है-हर बच्चा विशेष है। प्रत्येक बच्चा अलग ढंग से सीखता है, अपनी गति से आगे बढ़ता है और अपने भीतर ऐसी प्रतिभाएं समेटे होता है, जिन्हें केवल अंकों या रैंक तक सीमित नहीं रखा जा सकता। परीक्षाएं अपनी प्रकृति के अनुसार, बच्चे की क्षमता के एक सीमित पहलू को ही दर्शाती हैं। समग्र व्यक्तित्व के निर्माण के माध्यम से ही उसकी असल रचनात्मकता और उत्कृष्टता का विकास होता है। ये अंतर किसी भी तरह की कमी नहीं हैं, बल्कि यही एक विविध, सुदृढ़ और नवाचारी समाज की नींव है। यह दर्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.)-2020 के मूल में है। इसके ढांचे के तहत, शिक्षा प्रणालियों, पाठ्यक्रमों और मूल्यांकन प्रणालियों को एक वास्तविक बाल-केंद्रित दृष्टिकोण के अनुसार पुनर्गठित किया जा रहा है, जहां शैक्षणिक अध्ययन के साथ-साथ रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शारीरिक तंदुरुस्ती और नैतिक मूल्यों के प्रचार पर विशेष जोर दिया गया है। मूल्यांकन संबंधी सुधार भी इसी उद्देश्य को रेखांकित करते हैं। पहली बार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं अब साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों को अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए अधिक लचीलापन मिलेगा और उच्च-दबाव वाली एकल परीक्षा से जुड़ा तनाव कम होगा। 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड लागू किए गए हैं, जो न केवल बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हैं, बल्कि उसके सामाजिक-भावनात्मक और शारीरिक विकास को भी संपूर्ण ढंग से दर्ज करते हैं।

सत्ता की निष्कंटक राह बरास्ते सुनेत्रा की ताजपोशी

महाराष्ट्र की सत्ता पर पकड़ देश की आर्थिक ताकतों की नब्ज पर पकड़ बनाती है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी अपनी इस पकड़ को कमजोर होते नहीं देखना चाहती। इसलिए उसने सुनेत्रा को साधने में देर नहीं लगाई। इसके लिए एनसीपी के ही नेताओं को अपना औजार बनाया और सफल रही। वैसे भी शरद पवार उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जहां से उनके लिए गुंजाइश कम है। उनके पास सक्रिय रहने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। बेशक वे अब भी कमजोर हों, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे नहीं, शरद पवार ही हैं। सुनेत्रा को अपने खेमें में लाकर बीजेपी ने शरद की इस बची-खुची चुनौती भी खत्म करने में कामयाब रही है। सुनेत्रा के साथ से एकनाथ शिंदे के लिए महायुति से बाहर निकलने की सोचना या बीजेपी पर दबाव बढ़ाने का मौका खत्म हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति शिंदे के साथ के चलते सुनेत्रा की भी रहेगी। बीजेपी सुनेत्रा के जरिए शिंदे को संतुलित करेगी तो शिंदे के जरिए सुनेत्रा को काबू में रखेगी।

राजनीति जज्बात से नहीं, हालात के हिसाब से चलती है। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण इसका उदाहरण है। सुनेत्रा के आंसू अभी सूखे भी नहीं, पति अजित पवार के निधन के शोक से उबरना तो दूर की बात है। फिर भी उन्होंने सियासी तकाजे को ही प्राथमिकता दी और महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। पारिवारिक वज्रपात के बीच सिंहासन पर बैठने को लेकर उनकी आलोचना स्वाभाविक है, क्योंकि समाज के सोचने का अपना ढंग है। सियासी हस्तियों से भी उसे सामाजिक परंपराओं और पारिवारिक संस्कारों को अपनाने की उम्मीद रहती है। सुनेत्रा सामाजिक सवालों से बच नहीं सकतीं। लेकिन सवाल यह है कि सुनेत्रा की ताजपोशी से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर क्या वजह रही कि सुनेत्रा ने आनन-फानन में शपथ ले ली। महाराष्ट्र के राजभवन में जनवरी महीने के आखिरी दिन जो राजनीतिक इतिहास रचा गया, उसकी कहानी किसने लिखी थी। महाराष्ट्र में भले ही शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली हो, लेकिन राज्य की राजनीति के सबसे मंजे हुए खिलाड़ी शरद पवार हैं। यह बात छुपी हुई नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़ों के बीच सुलह और एकीकरण की बात चल रही थी। शरद पवार तो खुलकर स्वीकार भी कर चुके हैं कि उनकी ओर से जयंत पाटिल, अजित पवार से बात कर रहे थे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 12 फरवरी को दोनों पार्टियों के विलय पर अजित और शरद में सहमति हो चुकी थी। लेकिन अजित के न रहने के बाद समीकरण बदल गए। अजित के साथ गए अहम नेताओं प्रफुल्ल पटेल, आर आर पाटिल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं की आशंकाएं बढ़ गईं। उन्हें डर था कि अगर विलय हुआ तो शरद पवार की पार्टी पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। इसके चलते सुप्रिया सुले की पार्टी पर पकड़ बढ़ जाएगी। सुप्रिया के नियंत्रण में इन नेताओं का काम करना असहज होता। प्रफुल्ल कभी शरद पवार के बेहद नजदीकी होते थे। अजित के साथ जाकर एक तरह से उन्होंने शरद पवार के साथ दगाबाजी ही की है। उन्हें ज्यादा आशंका थी कि विलय के बाद पार्टी पर पकड़ होने के चलते शरद के बहाने सुप्रिया का चाबुक उन पर चल सकता है। लेकिन अगर पार्टी अलग रहती है और सुनेत्रा के हाथ कमान रहती है तो इन नेताओं की सियासी सेहत बनी और बची रह सकती है। यही वजह है कि अजित के निधन के चलते हुए आधिकारिक शोक की मियाद खत्म होते ही प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे नेता सक्रिय हो गए। विधायक दल की बैठक बुलाई गई और सुनेत्रा को तत्काल उसका नेता चुनकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार कर लिया गया। शरद पवार भले ही इस सियासी पटकथा का लेखक सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को मानते हों, लेकिन महाराष्ट्र के सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि असल में यह पटकथा राज्य की बीजेपी ने लिखा है। पटेल और तटकरे जैसे नेताओं ने सिर्फ इसे अमल में लाने में भूमिका निभाई है। सवाल उठ सकता है कि अगर सुनेत्रा शपथ नहीं लेतीं तो क्या बीजेपी की सियासी सेहत गड़बड़ा सकती थी, क्योंकि राज्य में बीजेपी के 132 और एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना के 57 विधायक हैं। राज्य में बहुमत के लिए महज 145 सीटें चाहिए होती हैं। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी की अगुआई वाली सरकार को कोई खतरा नहीं होने जा रहा था। अजित समेत एनसीपी के 41 विधायक पिछले चुनाव में चुने गए हैं। अजित के न रहने पर यह संख्या 40 रह गई है। लेकिन बीजेपी की चिंता दूसरी है। शरद पवार की राजनीतिक स्थिति भले ही ठीक ना हो, लेकिन जैसे ही दोनों एनसीपी का विलय होता, शरद ताकतवर होकर उभरते। महाराष्ट्र का यह चाणक्य एक बार फिर स्थापित होता और बीजेपी के लिए नई सिरदर्दी खड़ी हो जाती। शरद पवार इतने प्रभावी और सियासी रूप से तिकड़मी हैं कि बीजेपी के लिए संकट बनकर उभर जाते। उनकी प्रभावी सक्रियता के चलते शिवसेना के गुटों को भी एक करने की वे कोशिश कर सकते थे। भले ही यह सोच कल्पना लग रही हो, लेकिन एकबारगी स्वीकार कर लें कि ऐसा होता तो महाराष्ट्र की राजनीति कैसी होती। महाराष्ट्र में जिला परिषदों के चुनाव हो रहे हैं। पहले विधानसभा और बाद में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की अगुआई वाली महाविकास अघाड़ी को सफलता नहीं मिली।

अजित पवार के न रहने के चलते कांग्रेस को सक्रिय होना चाहिए था। अजित की अगुआई वाले जिला परिषद उम्मीदवार उनके न रहने की वजह से थोड़े आशंकित और निराश भी हैं। इस निराशा को कांग्रेस भुना सकती थी। वह एनसीपी के उम्मीदवारों पर डोरे डाल सकती थी और अपने उम्मीदवारों को नए जोश से भर सकती थी। अजित बेशक सत्ता में थे, लेकिन उन्हें विपक्षी खेमे के लिए अब भी हसरतभरी निगाह से ताकतवर नेता के रूप में देखा जा रहा था। अजित के न रहने के बाद विपक्षी नेतृत्व के लिए आसमान खुल गया है। शरद पवार की उम्र हो गई है। शरद के बाहर जाने के बाद से ही कांग्रेस राज्य में कमजोर हुई है। सुप्रिया सुले का नेतृत्व ऐसा नहीं है कि वह राज्यव्यापी प्रभाव हासिल कर पाएं। यह माहौल कांग्रेस के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। ऐसे माहौल में कांग्रेस को अपने ताकतवर नेतृत्व को स्थानीय स्तर पर आगे लाना चाहिए था। लेकिन वह ऐसा करती नहीं दिख रही। 2014 के बाद से उसने जिस नैरेटिव युद्ध की शैली को अपनाया है, राष्ट्रीय स्तर पर उसी युद्ध प्रक्रिया को जारी रखे हुए है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास फुर्सत नहीं है कि वह महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य की राजनीति के बारे में स्थानीय जरूरतों के लिहाज से सोचे और स्थानीय समुदायों के लिए उन्हीं के बीच से प्रभावी नेतृत्व उभारे। रणनीतिक लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी सभी दलों पर एक बार फिर बीस पड़ती नजर आ रही है। उसने सुनेत्रा को अपने खेमे में लाकर एक तीर से दो निशाने साध लिए हैं। उसने एनसीपी की ओर निश्चिंतता हासिल कर ली है, शरद पवार को एक बार फिर किनारे रखने में सफल हुई है और अपने लिए खतरा बनने की शरद की संभावनाओं को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी भी है। इसी वजह से केंद्रीय सत्ता के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली महाराष्ट्र की सत्ता मानी जाती है। माना जाता है कि कारपोरेट और औद्योगिक जगत पर सबसे ज्यादा पकड़ महाराष्ट्र के सिंहासन की होती है। मौजूदा राजनीति में आर्थिकी सबसे ज्यादा प्रभावी है। महाराष्ट्र की सत्ता पर पकड़ देश की आर्थिक ताकतों की नब्ज पर पकड़ बनाती है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी अपनी इस पकड़ को कमजोर होते नहीं देखना चाहती। इसलिए उसने सुनेत्रा को साधने में देर नहीं लगाई। इसके लिए एनसीपी के ही नेताओं को अपना औजार बनाया और सफल रही। वैसे भी शरद पवार उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जहां से उनके लिए गुंजाइश कम है। उनके पास सक्रिय रहने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। बेशक वे अब भी कमजोर हों, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे नहीं, शरद पवार ही हैं। सुनेत्रा को अपने खेमें में लाकर बीजेपी ने शरद की इस बची-खुची चुनौती भी खत्म करने में कामयाब रही है। सुनेत्रा के साथ से एकनाथ शिंदे के लिए महायुति से बाहर निकलने की सोचना या बीजेपी पर दबाव बढ़ाने का मौका खत्म हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति शिंदे के साथ के चलते सुनेत्रा की भी रहेगी। बीजेपी सुनेत्रा के जरिए शिंदे को संतुलित करेगी तो शिंदे के जरिए सुनेत्रा को काबू में रखेगी।

हमारी ज़िन्दगी कब सुधरेगी

निर्मला जी ने एक और बजट पेश कर दिया। यह उनका लगातार 9वां बजट था। उनसे अधिक केवल मोरारजी देसाई ने 10 बजट पेश किए थे, पर वह लगातार नहीं थे। मैं अर्थ शास्त्री नहीं हूं इसलिए बजट के गुण- दोष पर टिप्पणी नहीं कर रहा। यह नोट किया गया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 7.4व की अच्छी दर से तरक्की करेगी। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और कुछ सालों में जर्मनी को पछाड़ कर हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। यह उस देश के लिए मामूली उपलब्धि नहीं है जो कभी अपने लोगों का पेट भरने के लिए अमेरिका से PL 480 कार्यक्रम के अधीन अनाज के लिए निर्भर था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने कहा है कि दूसरे देशों से 'भीख मांगते' उनका सिर झुक जाता है और उन्हें शर्म आती है। भारत की वह हालत नहीं बनी। यह आज़ादी से लेकर अब तक हमारे नेतृत्व की सही सोच का परिणाम है। वर्तमान मोदी सरकार ने लगभग 12 सालों में देश को स्थिरता दी है जिस कारण भी देश तरक्की कर रहा है। हाल ही में हम ई-यू से बड़ी डील कर हटे हैं और डोनाल्ड ट्रम्प ने भी डील की घोषणा की है, पर इसका ब्यौरा अभी स्पष्ट नहीं। देश मजबूती से 2047 में 'विकसित भारत' के लक्ष्य की तरफ चल रहा है,ऐसा हमें बताया गया है। यह सब तो ठीक है, संतोषजनक है, पर ज़मीनी हकीकत तो यह है कि इन आंकड़ों से अलग आम भारतीय की ज़िन्दगी भी है जिसमें कोई सुधार नहीं हुआ। हम प्रदूषित शहरों में रहते हैं, जहां क्राइम बढ़ रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं,कूड़े-कचरे के ढेर हैं,पर कोई परवाह करने वाला नहीं क्योंकि चुनाव रोज़मर्रा के मसलों पर नहीं, भावनात्मक मुद्दों पर लड़े जाते हैं। धर्म पर बांटने के बाद जाति पर बांटने का भी प्रयास होता रहता है। दुख की बात है कि यूजीसी जैसी उच्च संस्था जिसकी ज़िम्मेवारी बच्चों का भविष्य संवारने की है, ने ही ऐसे नियम बना दिए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 'विभाजनकारी' और 'खतरनाक' करार दिया। नियम ऐसे थे कि कैम्पस के अंदर जातिगत बंटवारा हो सकता था। बड़ी अदालत ने रोक तो लगा दी, पर सवाल तो उठता है कि प्रयास ही क्यों किया गया । यह लेख मैं दिल्ली में लिख रहा हूं। चार दिन पहले मैं जालंधर से यहां सड़क के रास्ते आया था। विभाजन से पहले इसे कभी सड़क-ए-आज़म कहा जाता था। अंग्रेजों ने इसे जीटी रोड का नाम दिया और आज़ाद भारत में यह शेरशाह सूरी मार्ग बन गया। आजकल यह हा-1 कहा जाता है। इसका आकार बढ़ चुका है। दोनों तरफ तीन-तीन लेन हैं। नितिन गडकरी को ऐसे हाईवे बनाने का जायज़ श्रेय दिया जाता है। देशभर में हाईवे और सुपर हाईवे का जाल बिछ गया है लेकिन यह नहीं देखा जाता कि मैटीरियल कैसा लगता है, या हाईवे की मैंटेनेंस कैसी है जालन्धर से दिल्ली तक अब इस हाईवे पर झटके मिलते हैं। लालू प्रसाद यादव ने एक बार कहा था कि सड़कें एक प्रसिद्ध अभिनेत्री (नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वह सही नहीं है) के गाल जैसे मुलायम होंगी। पर अब तो गाल में गड्ढे पड़ गए हैं! असली समस्या है कि देश में वर्क कल्चर में सुधार नहीं हुआ। जिनका काम देखना है, वह जिम्मेवारी सही नहीं निभा रहे। बाबुओं की मानसिकता नहीं बदली। बाकी तबाही भ्रष्टाचार ने पूरी कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस'। अर्थात सरकार बढ़िया शासन देगी। पर आज भी काम करने की संस्कृति नहीं है जिसका दुष्परिणाम आम आदमी भुगत रहा है। मैं पिछले महीने मलेशिया की राजधानी कौलालम्पुर में था। सड़कें सचमुच उस अभिनेत्री की गाल की तरह मुलायम थीं। कहीं कोई हॉर्न नहीं बजाता, कहीं पुलिस वाला नज़र नहीं आता। वातावरण भी साफ-सुथरा था जबकि दिल्ली में आते ही प्रदूषण आपको पकड़ लेता है। गला खराब हो गया, नाक बहने लगी। देश की राजधानी, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। बीमारी का घर है। बाहर से लोग आने से घबराते हैं। कोई इलाज भी नहीं। यह कैसी गवर्नेंस है कि राजधानी में ही लोगों को बीमार होने और कईयों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है क्योंकि प्रदूषण को कम करना सरकारी प्राथमिकता में नहीं है जिस संसद ने 150 साल पुराने वंदे मातरम् पर एक दिन बहस में लगाया, उसके पास प्रदूषण पर बहस के लिए कोई समय नहीं था जबकि हर सर्दियों में बड़ी संख्या में नागरिक मरीज़ बन रहे हैं। और अगर आप बीमार हो गए तो किधर जाओगे सरकारी अस्पतालों की जो शोचनीय हालत है वह सबके सामने है। ठिठुरती सर्दी में देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स के बाहर खुले में मरीज़ों के सम्बन्धी सोने के लिए मजबूर हैं। ऐसे चित्र प्रकाशित हो चुके हैं, पर शासन को परवाह नहीं है। सरकार इलाज के बहुत से स्कीमें काम कर रही है, पर क्योंकि सरकारी अस्पतालों की हालत नहीं सुधरती इसलिए, नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 60फीसदी लोग प्राइवेट अस्पतालों में महंगा इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। बात वहीं आती है कि वर्क कल्चर कब संवेदनशील, कार्य कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा दिल्ली में राजपथ को 'कर्त्तव्य पथ' का नाम दे दिया गया है, पर कर्त्तव्य के प्रति भावना कब पैदा होगी बार-बार नवनिर्मित पुल वहां क्यों गिरते हैं बिहार में तो बरसात में एक दर्जन पुल बह गए, पर जनता ने उसी अक्षम सरकार को भारी बहुमत से निर्वाचित कर दिया। इंदौर को कई वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जा रहा है, पर वहां ही लगभग दो दर्जन लोग पानी पीने से मार गए क्योंकि पानी और सीवरेज मिल गए थे। सरकारी स्कूलों की हालत सब जानते हैं। केवल दिखावा होता है, पर बेहतर करने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया जाता। शायद इसलिए क्योंकि जिन की जिम्मेवारी इन्हें ठीक करना है उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। कुछ वर्ष पहले मुम्बई के पॉश इलाके में रहने वाले अभिनेता रितिक रोशन ने प्रेस में शिकायत की कि उनके नल में भूरे रंग का पानी आ रहा है। वहां भी पानी में सीवरेज मिल गया था। हर बरसात में हमारे बड़े शहर, दिल्ली, मुम्बई, बैंगलोर पानी में डूब जाते हैं। इसे प्रदूषण की तरह सामान्य समझा जाता है इसलिए स्थाई समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं की जाती।

बैंगलोर को कभी गार्डन सिटी कहा जाता था, पर अब वह खचाखच भरे ट्रैफ़िक और चरमरा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर का शहर बन चुका है। सुध लेने वाला कोई नहीं क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम कुर्सी की खींचातानी में लगे हुए हैं। हमारे शहर गारबेज, गड्ढों और ट्रैफ़िक के दुःस्वप्न हैं। टिकाऊ सड़कों से किसी की जेब नहीं भरती इसलिए खुदाई होती रहती है, टेंडर होते रहते हैं, सड़कें फिर बनाई जाती हैं।

पहली बरसात में गड्ढे पड़ जाते हैं। जनवरी की धुंध में ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार पानी से भरे निर्माणाधीन गड्ढे में गिर गई। सावधान करने के लिए न कोई बोर्ड था, न कोई बाड़ या चारदीवारी इसलिए वह सीधा पानी में चले गए और डूब गए। पिता को अंतिम फोन में उसने कहा, -मैं मरना नहीं चाहता-। नोएडा तो 'स्मार्ट सिटी' घोषित है। पर किसी अफ़सर ने नहीं देखा कि खुला असुरक्षित गड्ढा है और हादसा हो सकता है बिल्डर भी समझते हैं कि रिश्वत से उनका काम चल जाएगा, इसलिए नियमों का पालन नहीं करते। हर प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। सब कुछ ड्रोन से नज़र आ सकता है, पर रुकता क्यों नहीं अरावली के जंगलों को बचाने के लिए सुप्रीम को दखल क्यों देनी पड़ी सरकार ने तो नियम बदल दिए थे जिनका सहारा लेकर कटान चलता रहता और दिल्ली का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। नई समस्या बढ़ता क्राइम है। हर शहर में गैंग बन गए हैं जो लूटपाट करते हैं। मुम्बई में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हो कर हटी है। पंजाब में यह सामान्य बन चुका है। विदेश में बैठे या जेल में बंद गैंगस्टर फरौती की मांग करते हैं और न मिलने पर हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं।

कई परिवार तो इनके आतंक के कारण देश छोड़ने पर मजबूर हैं। इसके बारे कोई राष्ट्रीय नीति बनाने की ज़रूरत है। आशा है गृहमंत्री अमित शाह इस तरफ ध्यान देंगे। सरकार की पहली ज़िम्मेदारी नागरिक को सुरक्षा देना है। हमारे शहर असुरक्षित बनते जा रहे हैं। हम जो टैक्स देते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से क्या मिलता है हवा साफ नहीं, पानी साफ नहीं, रिश्वत अभी भी चलती है, शहर गंदे हैं। क्राइम और ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं। सुरक्षा नहीं है।

निर्मला जी का कहना है कि सरकारी खर्चा बढ़ने के लिए वह टैक्स का जाल और बढ़ाएंगी, पर क्या इससे हमारी ज़िन्दगी में सुधार आएगा जो भारतीय विदेश चला जाता है वह लौटना नहीं चाहता क्योंकि बाहर क्वालिटी ऑफ लाइफ' बेहतर बताई जाती है। हमारी तो राजधानी रहने योग्य नहीं रही। सरकार ने स्मार्ट सिटिज़ बनाई हैं, पर क्या एक भी शहर उस मायने में स्मार्ट है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ कब दुरुस्त करेंगी क्या समय नहीं आ गया कि इस तरफ़ ध्यान दिया जाए ताकि टैक्स देने वाला नागरिक महसूस कर सके कि उसे भी बदले में कुछ मिलता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने बत्रा ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैन्चशील एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/00862)

टफार्मेसी, एग्रीकल्चर और मेडिकल कॉलेज ने जीते क्रिकेट मैच

मुरादाबाद।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के टिमिट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की ओर से आयोजित इंटरकॉलिजिएट चैंपियनशिप- 2026 के आधा दर्जन क्रिकेट मुकाबलों में फार्मेसी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की टीमों ने धमाकेदार जीत दर्ज की। फार्मेसी कॉलेज ने फिजियोथैरेपी कॉलेज को 44 रनों, एग्रीकल्चर कॉलेज ने डेंटल कॉलेज को 115 रनों और मेडिकल कॉलेज ने फाइन आर्ट्स कॉलेज को 09 विकेट से मात देते हुए मुकाबले अपने नाम किए। फार्मेसी और फिजियोथेरेपी के मुकाबले में फार्मेसी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। फार्मेसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 151 रनों का पहाड़नुमा स्कोर बनाया। फॉर्मेसी की ओर से बल्लेबाज वीरेंद्र ने 31 गेंदों में 69 की तूफानी पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 2 बेहतरीन छक्के शामिल रहे। फिजियोथैरेपी की तरफ से सलमान ने 1 विकेट अपने नाम किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी फिजियोथेरेपी की टीम 12 ओवर में महज 106 रन बना पाई। फिजियोथैरेपी की ओर से फैजल ने 4 चौके की मदद से 35 रनों की पारी खेली। फार्मेसी की तरफ से आदित्य ने 3 ओवरों में 3 विकेट चटकाए। फार्मेसी के वीरेंद्र को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे और मुकाबलों में पैरामेडिकल कॉलेज ने नर्सिंग कॉलेज, एजुकेशन कॉलेज ने लॉ कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज ने इंजीनियरिंग कॉलेज को हराया। एग्रीकल्चर और डेंटल कॉलेज के मुकाबले में डेंटल

कॉलेज का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय बहुत महंगा साबित हुआ। एग्रीकल्चर की टीम ने ये मुकाबला 115 रनों से अपने नाम किया। एग्रीकल्चर ने 12 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 179 का विशाल स्कोर खड़ा किया। एग्रीकल्चर की तरफ से हर्ष राज ने 17 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्के की मदद से 54 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। हर्ष को बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मन ऑफ द मैच चुना गया। लक्ष्य का पीछा करने

टीएमयू में इंटरकॉलिजिएट चैंपियनशिप- 2026

उतरी डेंटल की टीम पूरे 12 ओवर खेलते हुए 9 विकेट के नुकसान पर महज 64 रनों पर ही ढेर हो गई। एग्रीकल्चर की ओर से अजहर ने 2 ओवर में 3 विकेट, जबकि डेंटल की ओर से अक्षित ने 18 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। इस धमाकेदार जीत के साथ एग्रीकल्चर अगले राउंड के लिए क्वालीफाई हुआ। फाइन आर्ट्स कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के मुकाबले में मेडिकल की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। 12-12 ओवर के इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए फाइन आर्ट्स की टीम 9 विकेट के नुकसान पर महज 59 रन ही बना सकी। फाइनआर्ट की तरफ से मुस्तफा ने 13 रन 11 गेंदों में 1 चौके की मदद से 13 रन बनाए और टीम के सबसे सफल बल्लेबाज साबित हुए। मेडिकल की तरफ से अभय सिंह ने 2 ओवर में × विकेट अपने नाम किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेडिकल की टीम ने मात्र 6.1 ओवरों में 1 विकेट खोकर 60 रनों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। फाइन आर्ट्स की ओर से 1 मात्र विकेट आकाश कोहली के नाम रहा। मेडिकल की ओर से शिवम ने 13 गेंदों में 18 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। इस दौरान शिवम ने कुल 2 चौके जड़े। बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मेडिकल के अभय सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

कुईयां वाली मस्जिद में सीरते तैयबा कार्यक्रम आज से

मुरादाबाद।

महानगर के मोहल्ला नई बस्ती कुइयां वाली मस्जिद में तीन रोज़ा बयानाते सीरत तैयबा प्रोग्राम और दस्तार बंदी मुनअकिद किया जा रहा है। कुइयां वाली मस्जिद के इमाम ओ खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान कासमी ने बताया कि प्रोग्राम के पहले दिन 6 फरवरी को हजरत मौलाना अंसार अहमद साहब कासमी बलगयामी 7 फरवरी को हजरत मौलाना अनीस अहमद साहब कासमी दिल्ली और 8 फरवरी को हजरत मौलाना आदम मुस्तफा साहब

तलबा की होगी दस्तारबंदी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान कासमी

फिरोजाबादी इस्लामिक लेक्चरार अबू हेरा कॉलेज फिरोजाबाद मुख्तलिफ उनवानात पर खिताब फरमाएंगें। औरतों के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम किया गया है। मोहसिने इंसानियत सरवरे आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा की सिरते तैयबा से खास ओ आम को आगाह करने के लिए मुनअकिद किए गए इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत के लिए सीरत ए कमेटी नई बस्ती की जानिब से अपील की गई है बताया गया है कि इस मौके पर प्रोग्राम के आखिरी दिन 8 फरवरी को कुइयां वाली मस्जिद के मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने वाले सात हाफिज ए कुरान सहित 31 तालिब इल्मों की दस्तारबंदी भी की जाएगी और उन्हें इनामात से भी नवाज़ा जाएगा

टीएमयू का यूपी संस्कृति विभाग के जैन विद्या शोध संस्थान के संग एमओयू साइन

मुरादाबाद।

उप्र के पर्यटन एवम् संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और टीएमयू के वीसी प्रो. वीके जैन की उल्लेखनीय मौजूदगी में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद और संस्कृति विभाग के जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ के बीच शिक्षण, शोध एवम् सास्कृतिक क्षेत्र में एमओयू साइन हुआ है। इस एमओयू पर टीएमयू की ओर से 'वाइंट रजिस्ट्रार डॉ. वैभव रस्तोगी, जबकि जैन विद्या शोध संस्थान की ओर से निदेशक अमित कुमार अग्निहोत्री ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर जैन साहित्य के विद्वान डॉ. एके जैन भी मौजूद रहे। टीएमयू की ओर से सेंटर फॉर जैन स्टडीज संचालित होता है।

इस सेंटर के तहत देशभर से इच्छुक युवा शोध करते हैं। एमओयू का मुख्य उद्देश्य जैन विधाओं का राष्ट्रीय संदर्भ में अध्ययन करना है। टीएमयू के शोधार्थी जैन तीर्थ स्थलों की सांस्कृतिक महत्व की परम्परा, आधारभूत मान्यताओं, मानवीय मूल्यों, कला अवशेषों का संरक्षण एवम् विश्लेषण की स्टडी कर सकेंगे। इसके संग-संग वे भारत और विदेशों में प्रचलित जैन विद्या के तुलनात्मक अध्ययन, उद्देश्यों के अनुरूप परिचर्चा, संगोष्ठी, व्याख्यान, सम्मेलन में भागीदारी कर सकेंगे। टीएमयू में संचालित जैन पुस्तकालय एमओयू होने के बाद अब जैन धर्म से संदर्भित ग्रंथों, पाण्डुलिपियों, माइक्रोफिल्मों आदि से और समृद्ध हो जाएगा। अब टीएयमू और जैन विद्या शोध संस्थान छात्र और संकाय विनिमय कार्यक्रम के संग-संग अंतर विषयी अध्ययन कर सकेंगे।

सरिया लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से दबकर दो मजदूरों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

मिर्जापुर । उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्टील की छड़ों से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दो मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि यह दुर्घटना बुधवार शाम को पदरी पुलिस थाना क्षेत्र के आम घाट के पास हुई। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान संजय (19) और अमन (18) के रूप में हुई है, दोनों कोटवा गांव के रहने वाले थे। थाना प्रभारी के मुताबिक, आम घाट के एक निवासी ने स्टील की छड़ें लाने के लिए ट्रैक्टर भेजा था और लौटते समय कुछ गांव वाले भी ट्रॉली पर बैठ गए। जब ट्रैक्टर ट्रॉली आम घाट के पास सड़क के ऊबड़-खाबड़ और खराब हिस्से से गुजर रही थी तभी वह पलट गई। सिंह ने बताया कि ट्रॉली पर सवार लोग समय रहते कूद गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन संजय और अमन स्टील की छड़ों के नीचे दब गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

बाल वाटिका के निपुण बच्चों को मिला सम्मान

फतेहपुर।

ब्लॉक संसाधन केंद्र शाह बहुआ में गुरुवार को 'हमारा आँगन हमारे बच्चे' कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता को सुदृढ़ करना तथा प्री-प्राइमरी स्तर पर बालवाटिका व्यवस्था को और मजबूत बनाना रहा। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ईसीसीई एजुकेटरों एवं नोडल शिक्षकों का संवेदीकरण व साक्षरता संवर्धन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बालवाटिका के निपुण बच्चों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। अतिथियों ने प्रारंभिक शिक्षा की नींव को मजबूत करने में बालवाटिका की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। डायट मेंटर शाइस्ता इकबाल, एसआरजी राजेश त्रिपाठी, सीडीपीओ रवि शास्त्री, एडीओ पंचायत विष्णु वर्मा, प्राथमिक शिक्षक संघ बहुआ के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सेंगर तथा खंड शिक्षा अधिकारी बहुआ हौंसिला प्रसाद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रारंभिक कक्षाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, बाल केंद्रित गतिविधियों और सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया। इस अवसर पर पूर्व एआरपी रेनू सिंह, एआरपी अभिषेक कुमार, राधे लाल, संग्राम सिंह, नरेश कुमार तिवारी, प्राथमिक शिक्षक संघ बहुआ के मंत्री संतोष कैथल, धीरेन्द्र सिंह, विमल कुमार, प्रभात कुमार, नीति सिंह, मोनिका वर्मा, सोनिया सिंह, वर्षा चौधरी, सविता, संजना, प्रियंका सहित कार्यालय के समस्त कर्मचारी एवं विकास खंड के शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के सफल आयोजन से क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा को लेकर नई ऊर्जा और सकारात्मक संदेश गया।

2017 के बाद गन्ना किसानों को तीन लाख करोड़ का भुगतान : सीएम योगी

लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में गन्ना किसानों की स्थिति में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 से 2017 के बीच 17 वर्षों में गन्ना किसानों को कुल 2.14 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि वर्ष 2017 से 2025 के बीच केवल 8-9 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी यह बातें राय ऋण संगोष्ठी एवं राय फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आधे समय से भी कम अवधि में पिछली सरकारों की तुलना में 86 हजार करोड़ रुपये अधिक भुगतान गन्ना किसानों को किया गया है। योगी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को 400 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान कर रही है। यह सरकार की किसान हितैषी नीतियों और ठोस निर्णयों का परिणाम है, जिससे अन्नदाता किसानों को सीधा लाभ मिला है। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश आज इथेनॉल उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। इसके साथ ही देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55 प्रतिशत हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश से आता है। चीनी उत्पादन में भी यूपी देश में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने समयबद्ध भुगतान, निवेश को बढ़ावा और उद्योगों के आधुनिकीकरण जैसे कई कदम उठाए हैं, जिसका सीधा लाभ किसानों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया जारी

मुरादाबाद।

संयुक्त आयुक्त उद्योग योगेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों हेतु एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारम्भ की गई है, जिसका संचालन उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। व्यक्तियों को अपना स्वंय का रोजगार एवं नई इकाई/उद्योग स्थापित करने हेतु बिना ब्याज के लोन की सुविधा बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई करायी जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी योजना के अन्तर्गत अधिक जानकारी एवं अपना आवेदन विभाग की वेबसाइट पर आन-लाइन प्रेषित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जनपद को आवंटित लक्ष्य 2800 के सापेक्ष अभी तक जनपद की बैंकों द्वारा 1686 प्रकरणों पर ही वितरण की कार्यवाही की गई जो अत्यन्त कम है, जबकि इस कार्यालय द्वारा बैंकों को पर्याप्त मात्रा में आवेदन पत्र अग्रसारित किये गये हैं, परन्तु बैंकों द्वारा लम्बित आवेदन पत्रों पर गम्भीरता से विचार नहीं किया रहा है जोकि अत्यन्त निराषाजनक है, जिसके कारण प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में लगातार जनपद पिछड़ रहा है। अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभ दिलाये जाने हेतु उद्योग विभाग द्वारा जनपद की तहसीलों में लागातार जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जनपद के व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य तथा अभ्यर्थी उ0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिये। अभ्यर्थी को ऋण आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता अंक पत्र, बैंक पासबुक, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि हो) की फोटोप्रति, कुटेशन एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन-लाइन अपलोड करना होगा।

योजना के अन्तर्गत सेवा/उद्योग क्षेत्र हेतु रू0 5.00 लाख तक की परियोजना मान्य होगी। अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता कक्षा 8 पास होनी चाहिये। सामान्य जाति हेतु स्वयं का अंशदान 15 प्रतिशत, पिछडी जाति हेतु 12.5 प्रतिशत व अनुसूचित जाति का अंशदान 10 प्रतिशत होगा। यदि पूर्व में किसी भी सरकारी योजना में अभ्यर्थी ने ऋण पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त किया होगा तो वह इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थी का ऋण आवेदन पत्र योजना के पोर्टल पर ऑन-लाइन प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त सम्बंधित बैंक को प्रेषित किया जायेगा। बैंक द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण कर नियमानुसार आवेदन को स्वीकृत एवं वितरित किया जायेगा।

लाभार्थी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का केवल मूलधन ही बैंक शाखा में चुकाना होगा। इस योजना में कोई ब्याज नहीं ली जायेगी। 04 वर्ष तक ऋण को सफलता पूर्वक चुकाने के पश्चात लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत सब्सिडी/छूट का लाभ भी प्राप्त होगा। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय-जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र निकट निकट 23 पी0ए0सी0, कांठ रोड, मुरादाबाद में सम्पर्क कर सकते है।

यूपी में बढ़ा राज्य पक्षी सारस का कुनबा, संख्या पहुंची 20 हजार के पार

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में राज्य पक्षी सारस का कुनबा बढ़ गया है। राज्य के 68 वन प्रभागों में हुई शीतकालीन गणना में इन परिंदों की संख्या बढ़कर 20 हजार 628 हो गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, प्रदेश में वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में उठाए जा रहे सार्थक कदमों के फलस्वरूप राज्य में साल दर साल सारस का कुनबा बढ़ता जा रहा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अनुराधा वेमुरी ने बताया कि राज्य में सारस की प्रतिवर्ष दो बार (ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन) गणना की जाती है। उन्होंने बताया, प्रदेश के 68 वन प्रभागों में हुई शीतकालीन गणना में कुल 20,628 सारस पाए गए। पिछले वर्ष हुई गणना में प्रदेश में सारसों की संख्या 19,994 थी। यानी इस बार इन परिंदों की संख्या में 634 की वृद्धि हुई है। वेमुरी ने बताया कि गणना से पहले वन विभाग कर्मियों द्वारा सारस बाहुल्य प्राकृतवास का सर्वेक्षण कर महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई। प्रदेश में शीतकालीन गणना कार्यक्रम में 10 हजार नागरिकों ने भी भाग लिया। वेमुरी ने बताया, साल 2023 में प्रदेश में 19,196 सारस थे। वर्ष 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 19,994 हो गई। अब इस शीतकालीन सत्र में प्रदेश में कुल सारसों की संख्या 20,628 दर्ज की गई है। वेमुरी के मुताबिक राज्यव्यापी गणना में इटावा वन प्रभाग में सर्वाधिक 3304 सारस मिले। इसके साथ ही 10 वन प्रभागों में प्रत्येक में यह संख्या 500 से अधिक रही। उन्होंने बताया कि वहीं, 29 वन प्रभागों में सारसों की संख्या 100 से 500 तक रही जबकि इतने ही वन प्रभागों में 100 से कम सारस मिले।

दिल्ली में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हैं लापता लेडीज, स्मार्ट पुलिस ने बताया कैसे बढ़ा यह आंकड़ा

नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लापता होने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले लगातार अधिक बनी हुई है। जनवरी 2026 के आंकड़े इस गंभीर स्थिति की ओर इशारा करते हैं। इस दौरान कुल 1777 लोग लापता हुए, जिनमें 1116 महिलाएं और 661 पुरुष शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि महिलाओं के मिलने का प्रतिशत पुरुषों से काफी कम रहा। दिल्ली पुलिस के अनुसार जनवरी 2026 में लापता हुए लोगों में से कुल 625 यानी 35.39 प्रतिशत लोगों का पता चल पाया है। लापता 661 पुरुषों में से 275 (41.60 फीसदी) मिल गए, जबकि 1116 लापता महिलाओं में से सिर्फ 354 (31.72 फीसदी) का ही पता चल सका। इसका मतलब यह है कि अभी भी कुल 1148 लोग यानी 64.60 प्रतिशत लोग लापता हैं। इनमें 58.59 प्रतिशत पुरुष और 68.72 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सालाना आधार पर लापता होने वाले लोगों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्ष 2024 में जहां 10,141 लोग लापता हुए थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 9,638 रह गई। इसी तरह कुल लापता मामलों में भी मामूली कमी आई है। भले ही लापता होने का आंकड़ा घट रहा है, लेकिन मिलने की दर में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी में लापता मामलों का फ्री रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू है। किसी बच्चे या व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिलते ही तुरंत मामला दर्ज किया जाता है, भले ही वह कुछ ही समय में घर लौट आए। कई बार जब लापता व्यक्ति खुद लौट आता है, तो लोग पुलिस या कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए इसकी सूचना नहीं देते। इसी वजह से डाटा में लापता मामलों की संख्या अधिक दिखाई देती है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में बच्चों या महिलाओं को चोरी करने वाला कोई संगठित गिरोह सक्रिय नहीं है। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध शाखा) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2024, 2025 और 2026 में लापता हुए लोगों के बारे में बुधवार को सभी थाना पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान 341 लोगों से फोन पर संपर्क किया गया, जिनमें से 45 लोग अपने घर लौट चुके हैं। पुलिस का कहना है कि लापता मामलों में समय पर सूचना देना बेहद जरूरी है, ताकि रिकॉर्ड अपडेट किया जा सके और वास्तविक आंकड़े सामने आ सकें। हर दिन थानों की रोजनामचा बुक में दर्ज होता है एक नाम– किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की बेटी। किसी के लिए यह सिर्फ एक एंट्री होती है, लेकिन किसी परिवार के लिए पूरी दुनिया थम जाने जैसा पल। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी महीने में 1116 महिलाएं लापता हुईं, लेकिन उनमें से सिर्फ 354 का ही पता चल सका।

कांग्रेस ने हमले की प्लानिंग की थी, इसलिए मैंने लोकसभा में पीएम की स्पीच टाली

लोकसभा में लगातार हंगामा : हालात बिगड़ते देख सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी- स्पीकर

नई दिल्ली ।

संसद के बजट सत्र के दौरान इन दिनों लोकसभा में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था, लेकिन विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के कारण यह संभव नहीं हो सका। हालात बिगड़ते देख सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में गंभीर और अहम बयान दिया है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जिस तरह का माहौल उस दिन लोकसभा में बना, उसमें कोई भी अप्रिय और अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा व्यवहार संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बिल्कुल विपरीत था।

विपक्षी व्यवहार को बताया अभूतपूर्व

ओम बिरला ने सदन को बताया कि लोकसभा के इतिहास में पहली बार उन्होंने इस तरह का आचरण देखा है। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने न केवल सदन के भीतर बल्कि अध्यक्ष के कार्यालय में भी जिस प्रकार का व्यवहार किया, वह संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं था। स्पीकर ने इसे संसदीय व्यवस्था पर काला धब्बा बताया और कहा कि अब तक राजनीतिक मतभेदों को कभी भी अध्यक्ष के कार्यालय तक नहीं ले जाया गया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सदन को सुचारू रूप से चलाने में सभी सांसदों का सहयोग आवश्यक है।

सदन में बने थे असाधारण हालात

बुधवार को लोकसभा में उस समय असामान्य दृश्य देखने को मिले, जब विपक्ष की महिला सांसद प्रधानमंत्री के संभावित भाषण से पहले बैनर लेकर उनके आसन की ओर बढ़ने लगीं। उस वक्त प्रधानमंत्री सदन में मौजूद नहीं थे और भाजपा सांसद पी. पी. चौधरी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रख रहे थे। हालात बिगड़ते देख सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी।

पीएम की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

स्पीकर ओम बिरला ने सदन में यह भी खुलासा किया कि जब प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तब उन्हें पुख्ता जानकारी मिली थी कि कांग्रेस के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री के आसन तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं सदन में ऐसे दृश्य देखे, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई थी। स्पीकर ने कहा कि यदि ऐसा होता तो यह न केवल अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होता, बल्कि देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को भी गहरा आघात पहुंचता।

इसी आशंका को देखते हुए उन्होंने एहतियातन प्रधानमंत्री से सदन में न आने का अनुरोध किया। ओम बिरला ने बताया कि सदन के नेता होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और सदन में नहीं आए। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे एक बड़े अप्रिय दृश्य को टालने में मदद मिली और सदन की गरिमा बनी रही।

स्पीकर ने दोहराया कि सदन के अध्यक्ष के रूप में उनकी यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे लोकसभा की उन परंपराओं और मर्यादा की रक्षा करें। गुरुवार को बजट सत्र के चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों में टकराव का माहौल बना रहा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रधानमंत्री सदन में मौजूद थे और बोलने वाले भी थे, लेकिन लगातार व्यवधान के चलते अंततः सत्ता पक्ष ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया। यह 2004 के बाद पहला मौका रहा, जब लोकसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन के बिना धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ।

कल पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था- स्पीकर ओम बिरला

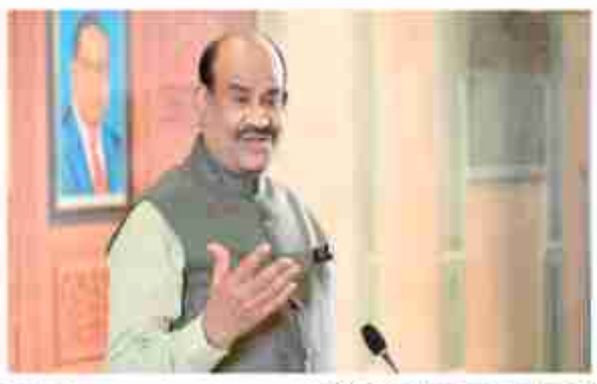

स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं पीएम मोदी- ओम बिरला के दावे पर भड़कीं प्रियंका, कहा- हमले की योजना की बात झूठ

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पीछे छिप रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने की किसी भी योजना के दावे को पूरी तरह झूठ बताया। उनकी यह टिप्पणी बिरला के लोकसभा में दिए गए बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि पक्की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने मोदी से सदन में भाषण देने के लिए न आने को कहा था, क्योंकि कई कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री को सीट के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित हरकत कर सकते थे।

सरकार स्पीकर से यह सब कहलवा रही है

गुरुवार को विपक्षी सदस्यों पर नाराजगी जताते हुए स्पीकर ने यह भी कहा कि बुधवार को उनके कार्यालय में कुछ सांसदों का व्यवहार अनुचित था और इसे उन्होंने उस घटना की एक काले धब्बे जैसा बताया। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार स्पीकर से यह सब कहलवा रही है, क्योंकि बुधवार को प्रधानमंत्री में सदन में आने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह सरासर झूठ है। प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने या ऐसी किसी भी बात का सवाल ही नहीं उठता। ऐसी कोई योजना थी ही नहीं। उन्होंने आगे कहा कि यदि सत्तापक्ष अपने सदस्यों को मनमानी करने, किताबें कोट करने और अनर्गल बातें कहने की छूट देगा, तो विपक्ष विरोध करेगा।

सरकार से पूछे तीखे सवाल

प्रियंका गांधी ने तीखे अंदाज में कहा, लेकिन अगर आप अपने सदस्यों को किताबें कोट करने, बकवास करने देंगे, तो विपक्ष विरोध करेगा। मुझे माफ करें, प्रधानमंत्री स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। वे स्पीकर से यह सब कहलवा रहे हैं क्योंकि कल उनमें सदन में आने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ इसलिए कि तीन महिलाएं उनकी बेंच के सामने खड़ी थीं...यह क्या बकवास है? कांग्रेस नेता ने मोठिया से अपील करते हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और सरकार से यह सवाल पूछें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या किसी सार्वजनिक स्रोत को उद्धृत करने से रोकने का कोई वैध आधार सरकार के पास है।

बिहार विधानसभा में तेजस्वी का बड़ा हमला, कहा- हमें हराने के लिए एनडीए ने फूंके 40 हजार करोड़

पटना । बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में उस वक्त गरमागरमी बढ़ गई, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्तारूढ़ एनडीए सरकार पर तीखा हमला किया। तेजस्वी यादव ने चुनावी खर्च और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाव में महागठबंधन को रोकने के लिए एनडीए ने बेहिसाब धनशक्ति का इस्तेमाल किया। विधान सभा में आज नेता प्रतिपक्ष शायराना अंदाज में अपनी बात शुरू करते हुए सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार विधान सभा चुनाव में जनता का विश्वास जीतने के बजाय धनबल का सहारा लिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के चुनाव में हमें हराने के लिए सत्तारूढ़ एनडीए ने करीब 40,000 करोड़ रुपये खर्च किए। यह पैसा किसका था और कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि इतनी भारी-भरकम राशि खर्च करने के बाद भी एनडीए को जनता के बीच संघर्ष करना पड़ा।

लोकतंत्र पर उठाए सवाल

भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ-साथ तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक ढांचे पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज बिहार में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने लोकतंत्र को भय के शासन में तब्दील कर दिया है। आज यहां विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और आम जनता को डराकर सत्ता चलाई जा रही है। तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुद्दों की राजनीति करने के बजाय डराने-धमकाने की राजनीति की जा रही है, जो बिहार के भविष्य के लिए घातक है।

सदन में जोरदार हंगामा

तेजस्वी यादव के इन बयानों के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने कड़ा ऐतराज जताया। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी के 40 हजार करोड़ वाले दावे को आधारहीन और हताशा में दिया गया बयान बताया। इस दौरान सदन में काफी देर तक शोर-शराबा होता रहा। तेजस्वी यादव की बात समाप्त होते ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा उठ खड़े हुए और उन्होंने लालू यादव को चारा चोर बोलते हुए जंगलराज की बात दुहराई।

मेघालय में खदान में विस्फोट, 10 लोगों की मौत,एक घायल

शिलांग। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में गुरुवार को एक अवैध कोयला खदान में डायनामाइट विस्फोट में दस लोगों की मौत हो गई। वहीं, एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है। यह कोयला खदान जिले के मिसिंगेट-थाम्को इलाके में है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। पूर्वी जयंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि दूरदराज के इलाके में स्थित इस खदान से चार शव बरामद किए गए हैं और एक झुलसे हुए व्यक्ति को उपचार के लिए शिलांग भेजा गया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और दमकल व आपात सेवाओं की टीमें मौके पर भेजी गईं। अधिकारियों ने कहा कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार, जिस पहाड़ी में अवैध खनन हो रहा था, विस्फोट के बाद उसका एक हिस्सा धंस गया, जिससे और खनिकों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब जिले में अवैध कोयला खनन को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। इसी थाम्को इलाके में पिछले साल 23 दिसंबर को भी ऐसा ही डायनामाइट विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट में दो खनिकों की मौत हो गई थी।

पश्चिम बंगाल : 4.06 लाख करोड़ का अंतरिम बजट

कोलकाता । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट पेश होने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र से पर्याप्त आर्थिक सहयोग न मिलने के बावजूद राय सरकार ने आम जनता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों और संसाधनों की कमी के बावजूद बंगाल सरकार ने ऐसा बजट तैयार किया है, जो समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला है। उनके मुताबिक यह बजट राज्य की विकासात्मक प्राथमिकताओं और सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वित्तीय अनुशासन पर जोर

ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किया गया बंगाल बजट वित्तीय अनुशासन का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद खर्च और आय के बीच संतुलन बनाए रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह बजट बंगाल की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा।

4.06 लाख करोड़ का अंतरिम बजट

पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में राज्य सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना 'लक्ष्मी भंडार' को और मजबूत करने का ऐलान किया गया। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत राय की 2.42 करोड़ महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ी हुई राशि फरवरी 2026 से लागू होगी। हालांकि, विपक्ष इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रहा है।

गिग वर्कर्स, कर्मचारियों और युवाओं पर फोकस

बजट में गिग वर्कर्स को राज्य की मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे 'स्वास्थ्यसाथी', के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भत्ते में 1000 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी बजट में शामिल है। ममता सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए भी नई पहल करते हुए पांच साल तक 1500 रुपये मासिक भत्ता देने की योजना का ऐलान किया है, जिसे जल्द लागू करने की बात कही गई है।

अजित पवार हादसा : खराब मौसम और तकनीकी गड़बड़ी बनी हादसे की वजह!

मुंबई । बारामती हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में अहम शुरुआती निष्कर्ष सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक, जांच में दो प्रमुख कारक सामने आए हैं जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। विस्तृत विश्लेषण अभी जारी है। सूत्रों के अनुसार, रनवे पर कम दृश्यता के बावजूद विमान ने लैंडिंग का प्रयास किया। जांचकर्ताओं ने पाया कि ऐसी परिस्थितियों में लैंडिंग का निर्णय लेना प्रारंभिक आकलन से सामने आए प्रमुख बिंदुओं में से एक है। दृश्यता की समस्या के साथ-साथ, प्रारंभिक जांच के दौरान एक संदिग्ध तकनीकी खराबी भी सामने आई है। अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि क्या किसी सिस्टम की खराबी के कारण

विमान के उतरने और लैंडिंग के दौरान उसके प्रदर्शन पर असर पड़ा होगा। अधिकारियों ने विमान के ब्लैक बॉक्स से डेटा रिकवर करना शुरू कर दिया है। पूरा डेटा प्राप्त और विश्लेषण हो जाने के बाद, पूरी जांच रिपोर्ट जारी की जाएगी। अधिकारियों ने जोर दिया कि अंतिम निष्कर्ष इस महत्वपूर्ण उड़ान डेटा पर निर्भर करेगा।

हरियाणा में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्षमता 3.67 लाख करोड़ रुपये, नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर किया जारी

चंडीगढ़ ।

'कृषि को लाभकारी बनाए बिना ग्रामीण समृद्धि संभव नहीं— मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

'नवाचार, तकनीक और वित्तीय सहयोग से बदलेगी हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था

'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने की दिशा में हरियाणा अग्रसर

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ऋण संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा ने देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बदलते समय के साथ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामने कई नई चुनौतियां भी आई हैं, जिनमें गिरता भूजल स्तर, मिट्टी की सेहत में गिरावट, छोटी जोत आकार, जलवायु परिवर्तन और उत्पादन लागत में वृद्धि प्रमुख हैं। इन चुनौतियों का समाधान परंपरागत तरीकों से नहीं, बल्कि नवाचार, तकनीक और संस्थागत वित्तीय सहयोग से ही संभव है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया वर्ष 2026-27 का स्टेट फोकस पेपर भी रिलीज किया, जिसमें हरियाणा की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्षमता 3 लाख 67 हजार करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अनेक समितियों को बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को लाभकारी बनाए बिना ग्रामीण समृद्धि संभव नहीं है। इसलिए हमें कम भूमि में अधिक उत्पादन और Per Drop-More Crop' के मंत्र को व्यवहार में उतारना होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए भूमिगत ढांचा भी उतना ही आवश्यक है, जितना की ऋण की सुविधा। इसके साथ-साथ सिंचाई, भंडारण, वेयरहाउसिंग, ग्रामीण सड़कें, बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सभी विकास की नींव हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए अलग से क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। किन्नू , अमरूद, स्ट्रॉबेरी, लीची आदि के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं ताकि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर नई आधुनिक खेती को अपनाए। किसान गन्ना की खेती अपनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि मिट्टी से मशीन और खेत से बाजार को पुख्ता बनाया जाये ताकि किसान द्वारा उगाई गई फसल को बेहतर बाजार मिल सके और साथ ही बेहतर भाव भी मिल सके। मुख्यमंत्री ने बैंकों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक पात्र किसान तक समयबद्ध, सरल और पारदर्शी तरीके से ऋण सुविधाएं पहुंचाएं ताकि, हमारे अन्नदाता बिचौलियों के चंगुल से मुक्त होकर आत्मनिर्भर बन सकें। इस कार्य में नाबार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नाबार्ड द्वारा कृषि एवं ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में लगातार सहयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एफ.एस.एम.ई., स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमिता और सहकारी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।

हरियाणा में 710 पैक्स कार्यरत है। इसके अलावा, सहकारी बैंकों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैक्स पर किसान को पूरा विश्वास है लेकिन पिछले कुछ समय में पैक्स की कार्यप्रणाली को लेकर किसानों में चिंता है। हमें किसानों के इस विश्वास को पुनः बहाल करना है क्योंकि ग्रामीण विकास में पैक्स का महत्वपूर्ण रोल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसानों द्वारा की जा रही खेती की जानकारी अपलोड करवाई गई।

किसानों को मांग के अनुरूप खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। खाद की कालाबाजारी रुकी और लगभग 700 करोड़ रुपये की सब्सिडी की भी बचत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी ने मिलकर विकसित भारत– 2047 के संकल्प को साकार करना है। इस कार्य में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी बैंक सुगम ऋण सुविधा उपलब्ध करवाएं, ताकि हमारा किसान आत्मनिर्भर बने।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत का मार्ग विकसित हरियाणा से होकर गुजरेगा। इसमें नाबार्ड, बैंक, राज्य सरकार और सभी हितधारकों के साझे प्रयासों से हम एक ऐसे हरियाणा का निर्माण करेंगे, जहां समृद्धि अंतिम पंक्ति तक पहुंच पाए। इस अवसर पर नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक निवेदिता तिवारी ने मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए विस्तार से नाबार्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि नाबार्ड द्वारा हरियाणा में वर्ष 2026-27 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत 3.67 लाख करोड़ रुपये की ऋण क्षमता का आकलन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है।

इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 1.32 लाख करोड़ रुपये तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये की ऋण संभावनाएं निर्धारित की गई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों, उद्यमियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वित प्रयास कर रही है, ताकि 'विकसित हरियाणा से विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार किया जा सके। उन्होंने कहा कि नाबार्ड द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत अब तक 18,393 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 14,066 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इन निधियों का उपयोग सड़कों, सिंचाई, नवीकरणीय ऊर्जा, अनाज भंडारण, पेयजल, स्वच्छता एवं विद्युत जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेट फोकस पेपर 2026-27 में फसल विविधीकरण, जल संरक्षण, माइक्रो इरिगेशन, बागवानी, वैल्यू एडिशन, जलवायु अनुकूल कृषि, किसान उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ करना, ग्रामीण एमएसएमई को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा और सामाजिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है ताकि सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार किया जा सके। इस अवसर पर एसीएस अनुराग आहलूवालिया, आयुक्त एवं सचिव सी जी रजनीकांत, कृष्ण शर्मा सहित बैंक प्रतिनिधि, अधिकारी आदि उपस्थित रहे।